अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते है।
– अज्ञात

विचार-प्रवाह
देहरादून, रविवार 24 नवंबर 2019
पेज थ्री
www.page3news.in

प्रदूषण पर बेफिक्री

हालत यह हुई कि मौजूदा सरकार का विरोध करने के क्रम में बीजेपी सांसदों को कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार का गुणगान करने में भी कोई समस्या नहीं हुई। मामले का दूसरा पहलू यह रहा कि दिल्ली के कुछ सांसदों ने इस चर्चा में शामिल होना भी जरूरी नहीं समझा।

रमा शाह

एक तरफ राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में प्रदूषण से लोगों का सांस लेना मुहाल हो रहा है, दूसरी तरफ राजनेताओं के लिए यह सियासी हिसाब चुकता करने का बहाना बन गया है। प्रदूषण की आड़ लेकर वे अपने विरोधियों को चित करने में जुटे हैं। नतीजा यह कि इस बीमारी का इलाज खोजना तो दूर, इस पर ढंग की बात भी नहीं हो पा रही। लोकतांत्रिक राजनीति में किसी मुद्दे पर पक्ष–विपक्ष का एक–दूसरे की आलोचना करना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मकसद कोई रास्ता खोलना होता है। मंगलवार को लोकसभा में प्रदूषण पर हुई बहस तो सिर्फ एक–दूसरे की टांग खिचाई करने की कवायद भर साबित हुई।

आम जनता के जीवन से सीधे जुड़े इस मुद्दे का भी हश्र अगर यही होना है तो फिर इस व्यवस्था में दूरदृष्टि के लिए कितनी गुंजाइश खोजी जाए? चर्चा में बीजेपी का सारा जोर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरने पर था। हालत यह हुई कि मौजूदा सरकार का विरोध करने के क्रम में बीजेपी सांसदों को कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार का गुणगान करने में भी कोई समस्या नहीं हुई। मामले का दूसरा पहलू यह रहा कि दिल्ली के कुछ सांसदों ने इस चर्चा में शामिल होना भी जरूरी नहीं समझा। हमारे सांसद प्रदूषण को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा पिछले हफ्ते ही मिल गया था, जब इस मसले पर बुलाई गई संसद की स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में 25 में से कुल 4 सदस्य पहुंचे और अधिकतर एमपी नदारद रहे।

बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने संसद में प्रदूषण पर चली बहस को लेकर सांसदों के अनमनेपन पर कहा कि संभव है बाकी सांसदों के क्षेत्र में प्रदूषण कम होने के कारण वे उपस्थित नहीं हुए और दिल्ली में स्थिति ज्यादा गंभीर है इसलिए यहां के सांसदों को आना पड़ा। दरअसल प्रदूषण को लेकर देश के समूचे राजनीतिक नेतृत्व का रवैया इसी हल्कपन का शिकार है। मीडिया या जुडिशरी से इस मामले में दबाव बढ़ता है तो आनन–फानन कुछ उपाय किए जाते हैं, फिर सब इसे भूल जाते हैं। निश्चित और स्थायी उपाय के बारे में सोचा तक नहीं जाता। लेकिन ध्यान रहे, चुनौती सिर्फ कुछ इलाकों की आबोहवा ठीक करने की नहीं है।

जलवायु परिवर्तन का भयावह संकट हमारे सामने खड़ा है, जिससे निपटने के लिए कई देशों में युद्ध स्तर पर अभियान शुरू हो गया है। लेकिन हमारे लिए यह आज भी टाइमपास है और हमारे नेतागण इसे हंसी–मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। जिन लोगों को लगता है कि प्रदूषण सिर्फ उत्तर भारत की समस्या है, उन्हें चेन्नै और केरल की बाढ़ को याद करना चाहिए और महाराष्ट्र के सूखे के बारे में भी सोचना चाहिए। मौसमों के अत्याचार से देश का कोई न कोई हिस्सा हर साल तबाह हो रहा है। हमें पर्यावरण के प्रश्न को व्यापकता में लेकर नीतिगत स्तर पर कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, जो तभी हो पाएगा जब सभी जन प्रतिनिधि क्षुद्र राजनीति छोड़कर इस पर एकजुट हों।

कुंडलिनी आग

टीएनएन

धर्म-दर्शन

बाबाजी ने कहा, "आग, सभी प्राचीन सभ्यताओं में पवित्र रही है। अग्नि, आग के देवता का वैदिक काल में रोजाना आह्वान किया जाता था। क्या आपने सोचा है क्यों आग इतनी महत्वपूर्ण है?" मैंने कहारू "व्यक्ति को आग की जरूरत खाना बनाने के लिए होती है और सर्दी में आग आपको गर्म और जंगली पशुओं को दूर रखती है। बाबाजी हंसे। "हां, हां, लेकिन इससे बहुत अधिक होता है। प्राचीन काल में, माचिस नहीं होती थी। आग उत्पन्न करने के लिए, व्यक्ति को अग्नि देवता के आह्वान के साथ सूखी लकड़ियों को एकसाथ रगड़ने के विधान से गुजरना पड़ता था। जब चिंगारी प्रकट होती थी वह सचमुच एक चमत्कार होता था। यह आग प्रदर्शित होने के पहले कहां थी, साधु ने पूछा। निश्चित रूप से वह लकड़ियों में छिपी थी और प्रदर्शन के लिए सही परिस्थिति की जरूरत होती थी।

संपादकीय

शांति की दिशा में

अफगानिस्तान सरकार, तालिबान और अफगान समाज के कुछ अन्य प्रतिनिधियों में अपने देश के भविष्य का एक खाका तैयार करने पर सहमति बन गई है। तालिबान हिंसात्मक गतिविधियां कम करने के लिए राजी हो गए हैं। कतर की राजधानी दोहा में हुई दो दिवसीय वार्ता के बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें सभी पक्षों ने गृहयुद्ध समाप्त करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। इसके साथ ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं के बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात भी कही। जर्मनी और कतर के प्रयासों से हुई इस वार्ता में कुछ सरकारी अधिकारियों समेत 60 सदस्यीय अफगान प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया था। हालांकि अफगान अधिकारी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर इसमें शामिल नहीं हुए थे। अमेरिका ने कहा है कि सितंबर में अफगानिस्तान में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं, इससे पहले वह तालिबान के साथ एक राजनीतिक समझौता करना चाहता है, ताकि विदेशी सुरक्षा बलों की वापसी शुरू हो सके। समझौते का आधार यह है कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से सुरक्षित और शांतिपूर्वक निकल जाएगी लेकिन बदले में विद्रोहियों को गारंटी देनी होगी कि न तो वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अलकायदा जैसी बाहरी ताकतों को करने देंगे, न ही खुद दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए खतरा बनेंगे।

देखना है, धुर–कट्टरपंथी तालिबान अपने मुल्क में जनतंत्र, मानवाधिकार, स्त्री स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर अपने पुराने रवैये में कितना बदलाव ला पाते हैं। सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शांति प्रक्रिया अफगानिस्तान को फिर एक कठमुल्ले समाज की ओर न धकेल दे।

यह 13 श्रम कानूनों को मिलाकर बना है। न्यूनतम वेतन से संबंधित संहिता को एक हफ्ता पहले स्वीकृति दी जा चुकी है। बाकी दो संहिताओं को शीघ्र मंजूरी दी जाएगी।

श्रम सुधार की पहल

मोहन कुमार

भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने और अगले पांच वर्षों में उसे पांच लाख करोड़ डॉलर का आकार देने के मकसद से सरकार ने व्यापक श्रम सुधारों का अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए उसने 44 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 श्रम संहिताएं बनाने का फैसला किया है। ये संहिताएं हैं– 1. न्यूनतम वेतन और कार्यगत सुरक्षा, 2. स्वास्थ्य एवं कार्यदशा, 3. सामाजिक सुरक्षा तथा 4. औद्योगिक संबंध। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और कार्यदशाओं से संबंधित बिल 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2019' के मसौदे को मंजूरी दे दी। यह 13 श्रम कानूनों को मिलाकर बना है। न्यूनतम वेतन से संबंधित संहिता को एक हफ्ता पहले स्वीकृति दी जा चुकी है।

बाकी दो संहिताओं को शीघ्र मंजूरी दी जाएगी। जहां तक स्वास्थ्य और कार्यदशा से संबंधित बिल का सवाल है तो इससे 40 करोड़ वर्कर्स लाभान्वित होंगे। छोटे कारखानों में कामगारों को अक्सर बिना नियुक्ति पत्र के काम करना पड़ता है। यह रास्ता अब बंद होने वाला है। हर साल श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच जरूरी होगी। नियोक्ताओं के लिए भी प्रक्रिया आसान की गई है। रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न को आसान

बनाया गया है। इनके लिए उन्हें अभी 10 से 21 तक फार्म भरने पड़ते हैं, लेकिन आगे एक–एक फार्म भरने से काम हो जाएगा। न्यूनतम वेतन से संबंधित संहिता पर श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार का कहना है कि इसके जरिए देश भर के लगभग 30 करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार मिलेगा।

बिल में 178 रुपये का न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया गया है। जिन राज्यों में इससे ज्यादा की व्यवस्था है वहां वह जारी रहेगी। वेतन हर महीने की नियत तारीख पर मिलेगा। इस प्रावधान से मजदूरों का शोषण रुकेगा क्योंकि आज भी कुछ राज्यों में दैनिक मजदूरी 50, 60 या 100 रुपये पर अटकी पड़ी है। हालांकि कानूनों को एकरूप बनाने के फैसलों पर कई संगठनों ने सवाल भी उठाए हैं। नैशनल कैंपेन कमेटी फॉर कॉन्स्ट्रक्शन वर्कर्स का कहना है कि इससे भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) एक्ट 1996 रद्द हो जाएगा, जिससे बीओसीडब्ल्यू बोर्ड बंद हो जाएंगे और लगभग चार करोड़ मजदूरों का पंजीकरण रद्द हो जाएगा।

भारतीय मजदूर संघ ने वेतन और सामाजिक सुरक्षा संबंधी लेबर कोड को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया है लेकिन औद्योगिक संबंधों से जुड़ी संहिता पर उसे गहरी आपत्ति है। उसका कहना है कि श्रम संगठनों के पदाधिकारियों के लिए पात्रता सरकार द्वारा तय किए जाने, हड़ताल करने का अधिकार सीमित करने, कर्मचारियों को एकतरफा तौर पर निकालने और एप्रेंटिस श्रमिकों को अलग करने जैसे प्रावधानों से श्रमिकों के अधिकारों में कटौती हुई है। अंततरू श्रमिकों की संतुष्टि ही उन्हें उत्पादन में बेहतर योगदान की ओर ले जाएगी, लिहाजा सरकार को सभी संहिताओं में यथासंभव सुधार करके ही उन्हें कानून की शक्ल देनी चाहिए।

सूडोकु नवताल-5175

★★★★★ सरल

2	9			5				4
4			2		7		8	
	1	6		8				3
8		5		9				7
3	6			2			1	9
1				3		5		2
5				7		6	3	
	3		1		8			5
9				6			2	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5174 का हल

7	8	1	6	9	4	2	5	3
2	6	4	5	3	6	1	7	9
5	3	9	1	2	7	4	6	8
9	5	8	7	4	1	3	2	6
1	2	3	9	5	6	7	8	4
4	7	6	3	8	2	9	1	5
3	9	7	2	6	5	8	4	1
6	4	2	8	1	9	5	3	7
8	1	5	4	7	3	6	9	2

अपना ब्लॉग

ज्यादा पालिथीन गायों के पेट में जाने से रोका

शिरीष खरे। आम दिनचर्या में प्लास्टिक के अंधाधुंध उपयोग से होने वाला प्रदूषण और उस से होने वाले नुकसान किसी शहर पर चाहे तेज तूफान की तरह नजर आता है। एक ऐसा तूफान जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। ब्रिटेन के एलन मैकआर्थर फाउंडेशन के अनुसार समुद्री विशेषज्ञों को आशंका है कि वर्ष 2050 तक समुद्र में मछलियों से अधिक प्लास्टिक होगी। दूसरी तरफ, अपने सुंदर समुद्री तटों के कारण पूरी दुनिया के पर्यटकों को लुभाने वाला गोवा राज्य भी प्लास्टिक–कचरे के प्रकोप से अछूता नहीं है। यहां भी यह विकराल रूप में विकसित हो रहा है। ऐसे में, गोवा की राजधानी, पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर बिचोलिम तहसील के अंतर्गत आने वाली शिरगाव की सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों ने एक नई उम्मीद जगाई है। यहां की तीन शिक्षिकाओं ने बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ऐसा मंत्र दिया है कि बच्चे तो बच्चे, बच्चों के परिजन, फेरीवाले, दुकानदार, पंच–सरपंच से लेकर पूरे के पूरा गांव ही 'प्लास्टिक हटाओ' अभियान में शामिल हो गया है।